लोकशक्ति अभियान का वक्तव्य

आज से ६८ वर्ष पहले हमारा देश एक लंबी अवधि की पराधीनता से मुक्त हुआ था और हमें राजनैतिक आजादी मिल गई। एक न्यायमूलक तथा समता मूलक समाज और एक आदर्श राष्ट्र बनाने की आकांक्षा ने भारत की करोड़ों की जनता को अभिभूत किया था ।

उस घटना के करीब छह दशक बाद आज भी देश का मन टूटा है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है, कि इन सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की उपस्थिति अब असंदिग्ध है। देश के कोने-कोने में और समाज के निचले तबके के लोग आज राजनैतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार के बारे में तथा मानवीय आत्मसम्मान के बारे में सचेत हुए हैं। इतने सचेत, कि आजतक कभी नहीं हुए थे। भारतीय जनता ने न सिर्फ तानाशाही थोपने की एक जबरदस्त कोशिश को नाकामयाब कर दिया, बल्कि सारे नए और पुराने अन्यायों के विरुद्ध कम बेशी मात्रा में जन सक्रियता का एक प्रवाह अभी भी चल रहा है।

लेकिन एक न्यायमूलक समाज, प्रशासन और अर्थनीति के निर्माण संबंधी जो सपने थे, वे भूमिसात हुए हैं। मानवीय प्रगति के मापदंडों पर आज के भारत की स्थिति अत्यंत शर्मनाक है। अगर देश की आधी आबादी के मन में भूख, बीमारी, अज्ञान और अपमान से उबरने का आज भी कोई विश्वास नहीं हो पाता है, तो इतने सालों की आजादी का जश्न मनाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जिस देश का विशाल जनसमूह इतनी दयनीय और असहाय स्थिति में रहता है, कि उसकी प्रतिरक्षा और अखंडता के बारे में दृढतापूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रतिरक्षा का पहला तत्व है, जनता का मनोबल। हथियार बाद में आता है।

इस लज्जाकार और असहनीय परिस्थिती का कारण खोजने के लिए हमारे हाथों में समय नहीं बचा है। निश्चय ही हमारी राजनैतिक पद्धतियाँ और विकास की नीतियाँ आरंभ से ही गलत रही हैं। एक ओर राज्य और राष्ट्र की राजधानियों में सत्ता को केंद्रित करने की राजनैतिक पद्धति गलत थी, उसे बदलना होगा। दूसरी ओर पूँजी आधारित बड़े उद्योगों और बड़े बड़े केंद्रीय प्रकल्पों को विकास का प्रतीक माननेवाली अर्थनैतिक पद्धति गलत थी, उसे रद्द करना पड़ेगा. गलत विकास नीतियों के फलस्वरूप न सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता बढ ती गई, बल्कि अंत में ऐसा दिवालियापन आया कि उसका बहाना बनाकर सरकार ने विदेशी पूँजी को खुली छूट देने की नीति अपनाई और विदेशी पूँजीपतियों की सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गई। अब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह विदेशी पूँजी के अधीन होती जा रही है। विदेशी पूँजी का लक्ष्य केवल देश की श्रमशक्ति का सम्यक उपयोग करने की जगह संसाधनों और बाजार पर कब्जा करना है। संसाधनों का अनावश्यक दोहन और पर्यावरण का विनाश करके तथा एक बाजारू संस्कृति को फैलाकर ही विदेशी पूँजी अपनी मनोकामना पूरी कर सकेगी। और इसीलिए हमारे देश पर प्रभुत्व कायम करना भी उनकी रणनीति है।

आज की तारीख पर ऊर्जा उत्पादन के उद्योग पर एकाधिकार प्राप्त करना विदेशी पूँजी का एक खास एजेंडा है। इस उद्योग पर एकाधिकार पाने का मतलब होगा, भारतीय राष्ट्र की ऊर्जा पर विदेशी नियंत्रण, ताकि यह राष्ट्र उसी के इशारे पर नाच सके। इसलिए, एनरॉन के विरुद्ध चल रहे जनसंघर्ष से लेकर आज के कंपनियों के खिलाफ चल रहे आदोलनों का हम विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। पर आज तो सेझ कानून और कम्पनियों को लूट की छूट देनेवाली नीतियाँ देश में हावी हैं। इसे रोकने में स्थानीय आदिवासी, किसान, आदिवासी लगे हुए हैं। इन आंदोलनों तथा सैंकडों स्थानों पर चल रहे विदेशी पूँजी विरोधी आंदोलनों के हम साथ हैं।

इस लज्जाकार और असहनीय परिस्थिती का कारण खोजने के लिए हमारे हाथों में समय नहीं बचा है। निश्चय ही हमारी राजनैतिक पद्धतियाँ और विकास की नीतियाँ आरंभ से ही गलत रही हैं। एक ओर राज्य और राष्ट्र की राजधानियों में सत्ता को केंद्रित करने की राजनैतिक पद्धति गलत थी, उसे बदलना होगा। दूसरी ओर पूँजी आधारित बड़े उद्योगों और बडे-बडे केंद्रीय प्रकल्पों को विकास का प्रतीक माननेवाली अर्थनैतिक पद्धति गलत थी, उसे रद्द करना पड़ेगा. गलत विकास नीतियों के फलस्वरूप न सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता बढ ती गई, बल्कि अंत में ऐसा दिवालियापन आया कि उसका बहाना बनाकर सरकार ने विदेशी पूँजी को खुली छूट देने की नीति अपनाई और विदेशी पूँजीपतियों की सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गई। अब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह विदेशी पूँजी के अधीन होती जा रही है। विदेशी पूँजी का लक्ष्य केवल देश की श्रमशक्ति का सम्यक उपयोग करने की जगह संसाधनों और बाजार पर कब्जा करना है। संसाधनों का अनावश्यक दोहन और पर्यावरण का विनाश करके तथा एक बाजारू संस्कृति को फैलाकर ही विदेशी पूँजी अपनी मनोकामना पूरी कर सकेगी। और इसीलिए हमारे देश पर प्रभुत्व कायम करना भी उनकी रणनीति है।

आज देश की बहुसंखय सामान्य जनता, बुद्धिजीवी भ्रष्टाचार के विरोध में खडी हो रही है। उसमें उत्साह एवं लगन है। इसे एक सखत लोकपाल कानून से तथा स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के विरोध में घोटाले निकालनेवाली प्रक्रिया चलाने की शासकीय नहीं, कार्पोरेट या बिल्डरों के भ्रष्टाचार भी, जो जमीन, खनीज, जल संसाधनों के विकृत हस्तांतरण से हो रहा है, उसे निपटने का संघर्ष, जनआंदोलनों को जनशक्ति के दबाव, कानूनी-मैदानी स्तरपर करना होगा। हमें स्वयं को भी बदलकर इस विकृति को दूर करना होगा। लोकपाल बिल के आंदोलन का समर्थन करते हुए, एक कानून की मर्यादा हम जानते हैं। हम व्यापक परिवर्तन की लडाई में ही भ्रष्टाचार का मुद्दा महत्वपूर्ण मानकर आंदोलनों के द्वारा भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ जंग छेडना चाहेंगे।

इन सारे आंदोलनों में अंततोगत्वा भारतीय जनता को भी कामयाबी मिलेगी--- यह हमारा दृढ़ विश्वास है। इसलिए भविष्य के निर्माण के बारे में हम अपनी नीति का ऐलान करते हैं, जिसका मूल-मंत्र होगा, स्वदेशी, सादगी, समता और स्वशासन। विदेशी पूँजी के बहिष्कार के द्वारा ही देश की श्रमशक्ति का महत्व बढेगा। हर-एक सक्षम व्यक्ति को काम देना केवल एक लोककल्याण का कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि यह विकास की अनिवार्य शर्त होगी। विलासिता और उपभोक्तावाद के बहिष्कार के द्वारा जनसाधारण की जरूरतों

के लिए उत्पादन बढाने का रास्ता खुल जाएगा तथा कथित देशी पूँजीवाद भी नहीं टिक पाएगा। अपने बचाव के लिए इसी देशी पूँजीवाद ने विदेशी पूँजी को न्यौता दिया है। अतः विदेशी पूँजी का विकल्प देशी पूँजीवाद नहीं हो सकता।

विकास के जिस संकट से आज हम गुजर रहे हैं, दुनिया के अधिकांश तथाकथित विकासशील देश भी इसी संकट का सामना कर रहे हैं। अपनी-अपनी लडाइयाँ लड रहे है। उन देशों में चल रहे जन-आंदोलनों के साथ हमारी समान बिरादरी का संपर्क स्थापित करेंगे, ताकि विश्व की सारी गरीब और मेहनतकश जनता एकताबद्ध होकर भूमंडलीकरण के विरुद्ध चल रही लडाई को तेज कर सकें और पूँजीवादी भूमंडलीकरण और कम्पनीकरण के मुकाबले वैकल्पिक विकास की एक नई अंतर्राष्ट्रीयता के घटक विश्व के वे सारे जन आंदोलन होंगे, जिनको तलाश है, एक ‘नई विकास पद्धति' की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जो विकासशील देशों के आपसी आंदोलन, संवाद, प्रयोग और विचार मंथन होगा, उसे एक नई प्रौद्योगिकी (ज्मबीदवसवहल) का जन्म होगा, जो विज्ञान पर आधारित होगा और विकेंद्रित उद्योगों का औजार होगा। संघर्ष के साथ रचना में विकल्प मार्ग भी परिवर्तन का आधार होगा।

साधारण जनता स्थानीय इकाइयों में ही वास करती है। अतः उसको गाँव या कस्बा जैसी स्थानीय इकाइयों को ही आर्थिक उत्पादन और औद्योगीकरण के लिए बुनियादी क्षेत्र माना जाना चाहिए। उस क्षेत्र के संसाधानों से संबंधित अधिकार और दायित्व वहाँ की स्थानीय जनता का ही होगा। स्थानीय जनता के जीवन तथा प्राथमिक जरूरतों के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता होगी, उसका उपयोग वहाँ होने के बाद ही उनका उपयोग जिला, राज्य या राष्ट्र स्तर पर हो सकता है। स्वशासन का अधिकार और दायित्व भी गाँव का ही होगा। यानी लोगों की भागीदारी से प्रशासन का जितना काम हो सकता है, वह गाँव का विषय होगा। उसके बाद जो भी प्रशासन के काम बच जाते हैं, उनके संचालन का दायित्व जिला, राज्य, राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्थाओं को सौंपा जाएगा। विकास और प्रशासन के इस प्रकार के संयोजन से राजनीति (च्वसपजपल) और अर्थनीति (म्बवदवउल) की एक वैकल्पिक संरचना खड़ी होगी। २१वीं सदी की एक विशेषता यह होगी, कि वैकल्पिक विकास तथा वैकल्पिक शासन की एक नयी संरचना उभरेगी। कई देशों में इस नयी संरचना का शुभारंभ होगा, और इसी से नई सभ्यता की शुरूआत भी होगी।

एक नई सभ्यता की शुरुआत करने का दावा हम तब तक नहीं कर सकते, जब तक कि भारत में प्रचलित मौजूदा पतनशील सामाजिक व्यवस्था का हम अंत नहीं कर देते। पुरुष-प्रधानता सारी दुनिया में एक सामाजिक विकृति है। लेकिन उसके साथ-साथ जातिभेद और सांप्रदायिक विभाजन, कहीं उभरे प्रांतवाद की प्रथाओं ने मिलकर भारतीय संस्कृति और समाज को कलंकित कर दिया है। वैकल्पिक विकास के लिए ग्राम-राज्य की स्थापना करनेवालों को सचेत होना पडेगा कि जिसे हम गाँव कहते हैं, वह आज एक अन्यायपूर्ण, विषमतापूर्ण इकाई बन गई है। अतः ग्राम-राज्य निर्माण और समाज परिवर्तन की प्रक्रियाएँ एक साथ चलेंगी।

समाज परिवर्तन, वैकल्पिक विकास और ग्राम स्वशासन निर्माण के इन तीन व्यापक दायरों के अंदर सैंकड़ो ऐसी समस्याएँ और चुनौतियाँ आँखों के सामने हैं, जिनके मुकाबले में हमें हजारों आंदोलन करने पडेंगे। भारत के विशाल बुद्धिजीवी वर्ग को यह एहसास होना चाहिए कि सब मिलकर और मन को ऊँचा उठाकर हम सारी चुनौतियों का सामना कर पाएँगे। गरीबी से जुडी हुई बेरोजगारी, भूमी सुधार, महँगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण की समस्याएँ, सामाजिक स्तर पर दलित, महिलाएँ और सांप्रदायिकता की समस्याएँ, संस्कृति में संवेदनहीनता, हिंसा, अश्लीलता, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, आत्मकेंद्रीयता की समस्याएँ, राजनीति में भ्रष्टाचार का अभूतपूर्व उत्थान, अपराधीकरण, दलीय जनतंत्र का खात्मा, जातीयता, अलगाववादिता की समस्याएँ, प्रशासन में अपारदर्शिता, जवाबदेही शून्यता, न्याय में विलंब आदि की समस्याएँय इन सहस्त्र समस्याओं में से हर-एक समस्या महत्वपूर्ण है और तत्काल प्रतिकार की माँग करती है। असल में आज मनुष्य सहस्त्र बाहुवाली एक दानवीय व्यवस्था की चपेट में है, तो लोकशक्ति को भी सहस्त्रबाहु होकर उसका सामना करना पडेगा। अन्याय विरोधी प्रवृत्तियाँ समाज के हृदय में छिपी हुई हैं और उत्साहहीनता के वातावरण में दब रही हैं। उन अन्यायविरोधी प्रवृत्तियों के जागृत और एकत्रित होने से एक जनक्रांति का उदय होगा और इतिहास का नया मोड शुरू हो जाएगा।

(इस वक्तव्य का मूल २२.०४.१९९७ को किशन पटनायक; मेधा पाटकर, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय; स्वामी अग्निवेश, बंधुआ मुक्ति मोर्चा; अमरनाथ भाई, सर्व सेवा संघ; मुकुंद कुलकर्णी, अभ्यास मंडल, इंदौर; सदाविजय, आंतरभारती; अविनाश धर्माधिकारी; मनी, युवा, मुंबई; विजय, भारत जन आंदोलन; के द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में तैयार किया गया था। बाद में ३ अगस्त २०११ को जनांदोलनो के राष्ट्रीय समन्वय के द्वारा बुलाई गयी वर्धा, महाराष्ट्र और अक्टूबर ३१ एवं नवम्बर १, दिल्ली की बैठक में बदले हुए समय के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जोड़े गए.)

****

देश के अन्य संगठनों, संस्थाओं, नागरिकों से आग्रह है की आप भी इस अभियान में शामिल हों. योगदान करें. एक कार्यकर्ता बने. आर्थिक सहयोग करें. विचारों के प्रचार प्रसार में मदद करें और अभियान को सफल बनाये |

जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय

संपर्क करें : 6/6, जंगपुरा बी, मथुरा रोड, नयी दिल्ली 110 014 फोन : 011 24374535 | 9818905316 | 9718479517

napmindia@gmail.com | www.napm-india.org

Join us on facebook NAPM | Twitter @napmindia